राजस्थान समसामयिकी जुलाई, 2026

संजीव Telegram, App एवं वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह;
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव App एवं वेबसाइट से आप
Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी जुलाई, 2026
(Current News from Daily Newspapers)

Newspaper of 1 July, 2026

वीबी-जी राम जी योजना लॉन्च हुई; मनरेगा से 10% ज्यादा मजदूरी मिलेगी; देशभर में 1 जुलाई से मजदूरी की नई दरें लागू–

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए 'विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट' (वीबी-जी रामजी) लागू कर दिया है। नया कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो गया। इसके साथ ही मजदूरी की संशोधित दरें भी लागू हो गई हैं। मनरेगा में राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 रुपए प्रतिदिन थी। वीबी-जी रामजी में यह बढ़कर 337.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है। यानी औसतन 28.6 रुपए रोजाना ज्यादा मिलेंगे। प्रतिशत के हिसाब से यह 10% से अधिक बढ़ोतरी है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इस योजना के तहत अधिसूचित मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी।

नगालैंड और अरुणाचल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी–सरकार के मुताबिक अब उन 21 राज्यों को फायदा होगा, जहाँ पहले मजदूरी 300 रुपए से भी कम थी।

- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़ा सुधार हुआ है।
- हरियाणा में अब मजदूरी 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन हो गई है।
- सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अरुणाचल और नगालैंड में 24.5% बताई है। सिक्किम की हाई एल्टीट्यूड ग्राम पंचायतों में 450 रुपए प्रतिदिन।

राजस्थान में पुराना वाहन बदलने पर रोड टैक्स में 100% तक छूट मिलेगी; केन्द्र सरकार की नया सफर योजना में राजस्थान-एनसीआर को बड़ी राहत मिली–

हाल ही में सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और पुराने प्रदूषणकारी व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से फैसला लिया है। केन्द्र सरकार की 'नया सफर योजना' के तहत पात्र वाहनों को बदलकर नए बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ने एकमुश्त कर और मोटर वाहन कर में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट की अधिसूचना जारी की है। यह फायदा उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा जिन्होंने अपना वाहन राजस्थान से खरीदा है। आदेश ट्रांसपोर्ट विभाग के संयुक्त सचिव ओम प्रकार बुनकर की ओर से जारी किया गया।

किस वाहन पर कितनी छूट मिल सकेगी

- **पुराना वाहन स्क्रैप करने पर :** नए BS-6 या ईवी रजिस्ट्रेशन पर वन टाइम टैक्स में 100% की छूट। अगले 10 वर्षों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स भी 100% माफ रहेगा।
- **सैकंड हैंड BS-6 वाहन खरीदने पर :** वन टाइम टैक्स में 50% और 10 सालों के मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी।
- **नया BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर :** वन टाइम टैक्स में 100% की छूट और 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की राहत मिलेगी।
- **रजिस्टर्ड BS-6 वाहन ट्रांसफर कर खरीदने पर :** वन टाइम टैक्स और 10 साल के मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट का लाभ मिलेगा।
- गौरतलब है कि टैक्स छूट का लाभ तभी मिलेगा जब नया वाहन राजस्थान में खरीदा हो।
- स्क्रैप पुराने वाहन के बदले ली जाने वाली नई गाड़ी उसी कैटेगरी (जैसे-लाइट मीडियम या हैवी व्हीकल) की होनी चाहिए।

Newspaper of 2 July, 2026

29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा की सौगात मिली; अब राजस्थान में वॉट्सऐप से घर बैठे 103 सरकारी सुविधाएँ मिल रही–

1 जुलाई, 2026 को आरआईसी जयपुर में 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा की सौगात दी। इसके जरिए वर्तमान में प्रदेश के लोग वॉट्सऐप नंबर 94610-62705 पर Hi भेजकर 103 सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं-

वॉट्सऐप सेवा से ये काम होंगे–

- बिजली, पानी के बिल जमा करा सकेंगे एवं अन्य कार्य करना सकेंगे।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट समेत कई दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- मूल निवास, जाति, जन्म, मृत्यु-प्रमाण पत्र बना सकेंगे।
- राशन कार्ड जैसे प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाएँ मिलेंगी।
- पुलिस विभाग की सेवाएँ और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी।

Newspaper of 3 July, 2026

■ **दूधिया सफेद 'नुकरा' घोड़े को वैज्ञानिक पहचान मिलेगी; राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की–** बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (एनआरसीई) ने पहली बार 'नुकरा' (सफेद) घोड़े की इस नस्ल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि सभी तकनीकी औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो नुकरा देश की नौवीं आधिकारिक पंजीकृत घोड़ा नस्ल बन जाएगा। वर्षों से इस नस्ल के सरंक्षण और वैज्ञानिक मान्यता के लिए किए जा रहे प्रयास अब निर्णायक चरण में पहुँच गए हैं। अब सर्वेक्षण के तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल में आधिकारिक पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा।

देश में 15 हजार नुकरा घोड़े : देश में करीब 15 हजार नुकरा घोड़े हैं। इनमें सबसे अधिक नौ हजार पंजाब, राजस्थान में तीन हजार नुकरा घोड़े पाए गए हैं। शेष संख्या अन्य राज्यों में फैली हुई है। अकेले बीकानेर जिले में लगभग 200 नुकरा घोड़े मौजूद हैं।

देश में घोड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें–मारवाड़ी, मणिपुरी, जांस्कारी, भीमथाड़ी, काठियावाड़ी, स्पीति, भुटिया, कच्छी सिंधी

अलग नस्ल के प्रमुख कारण–

- विशिष्ट शारीरिक बनावट और शांत स्वभाव।
- दूधिया सफेद रंगत, गुलाबी नाक और होंठ तथा मजबूत एवं संतुलित कद-काठी।
- तेज चाल और अधिक सहनशक्ति।
- कानों का विशेष लचीलापन।
- ऊँचाई लगभग 160 से 170 सेंटीमीटर।
- शरीर पर एक-दो काले निशान, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'फुलकारी' कहा जाता है।

■ **2 जुलाई, 2026 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित किया तथा राजस्थान के सीएम ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से इस कार्यक्रम में वीसी के जरिये जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबी जी रामजी योजना के राज्यस्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित किया।**

Newspaper of 5 July, 2026

■ **राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में पहली ग्रीनफील्ड और 13वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ; इसके साथ-साथ जयपुर मेट्रो 2.0 का शिलान्यास तथा जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ–**

4 जुलाई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक और पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 'उड़ान' को शुरू किया। वर्चुअल रूप से जयपुर मेट्रो 2.0 की आधारशिला रखी।

- पचपदरा देश की 24वीं रिफाइनरी है। नई रिफाइनरी की देश के कुल कच्चे तेल प्रोसेसिंग में 3.5 फीसदी की हिस्सेदारी होगी। जबकि, यह प्रोसेसिंग क्षमता के लिहाज से देश की 13वीं बड़ी रिफाइनरी होगी।
- देश में सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर कॉम्प्लेक्स (68.2 एमएमटीपीए) की है। एकल रिफाइनरी के रूप में नायरा एनर्जी की वडिनार सबसे बड़ी है। राजस्थान की रिफाइनरी क्षमता मध्य श्रेणी में है। अभी देश में कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 258.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। कच्चे तेल रिफाइनरी वाला राजस्थान देश में 15वाँ राज्य है।
- पचपदरा स्थित देश की पहली अत्याधुनिक बीएस-6 मानक वाली रिफाइनरी होगी। रिफाइनरी के अधिकांश रिएक्टर, कॉलम, भारी टैंक भारत में ही बने हैं। लेकिन कंट्रोल सिस्टम, हाई प्रेशर कंप्रेसर के लिए अमेरिका, जापान, यूरोप से तकनीक लाई गई।
- अब राजस्थान केवल कच्चा तेल निकालने वाला राज्य नहीं रहेगा। वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट (जैसे पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलिमर) बनाने वाला हब बनेगा। प्लास्टिक, केमिकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर मेट्रो 2.0 (प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ 41 किमी.) का वर्चुअली शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट 4 पैकेजों में पूरा होगा। प्रत्येक पैकेज का सिविल कार्य 36 माह में पूरा होगा। जबकि पूरी परियोजना पूरा होने में साढ़े 5 साल लगेंगे। इसमें कुल 36 स्टेशन बनेंगे। ₹13,037 करोड़ की इस परियोजना का आधा हिस्सा केन्द्र सरकार और आधा राजस्थान सरकार वहन करेंगी। सबसे पहले प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किमी. कॉरिडोर बनेगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। भवन में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा से लेकर वीर दुर्गादास व पर्यावरण के लिए जान न्यौछावर करने वाली अमृता देवी को दर्शाया गया है।

Newspaper of 7 July, 2026

- **भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) उदयपुर ने प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच अपने महत्त्वाकांक्षी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) प्रोग्राम की वर्चुअल शुरुआत की है। यह देश का पहला आईआईएम बन गया, जिसने हिन्दी में बैचलर कोर्स शुरू किया है। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 6 जुलाई, 2026 को इसकी वर्चुअल शुरुआत की। आईआईएम उदयपुर के निदेशक डॉ. अशोक बनर्जी हैं।**
- **दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय का 5वाँ स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ–**

6 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय का 5वाँ स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राजस्थान को निम्न सौगातें मिलीं–

- 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास हुआ।
- 50 गोदामों का लोकार्पण हुआ।
- 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण हुआ।

इस दौरान जयपुर में बनने वाले 'सहकार वन' का ई–भूमि पूजन हुआ। यह जयपुर के सुमेल गाँव में बनेगा तथा 66 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। इसमें खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे वृक्ष लगाए जाएंगे। मियावाकी और सामान्य प्रणाली से वृक्षारोपण होगा।

Newspaper of 8 July, 2026

- **राजस्थान मे होमस्टे पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन हुआ; एसएसओ पोर्टल से ही आवेदन होंगे–**

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्णत: ऑनलाइन कर दिया है।

- अब राज्यभर में गृह स्वामी होमस्टे पंजीकरण के लिए आवेदन राजस्थान सिंगल साइन–ऑन (एसएसओ) पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
- राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026 के तहत निजी आवासों में पर्यटकों के लिए अधिकतम आठ कमरों तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
- होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) में मकान मालिक के रहने की अनिवार्यता समाप्त कर केयरटेकर के माध्यम से भी होम स्टे का संचालन किया जा सकेगा।
- योजना के अनुसार समस्त दस्तावेजों के पूर्ण होने पर सात दिनों में अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी तथा आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Newspaper of 9 July, 2026

- **राजस्थान सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में फेसलेस एवं रैंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू की–**

राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में फेसलेस एवं रैंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू करने की अभिनव पहल की है, जो देश में अपनी तरह की अग्रणी व्यवस्था है।

- इस नई व्यवस्था के तहत कर विवरणियों की स्क्रूटनी के लिए प्रकरणों का चयन एवं आवंटन कम्प्यूटर आधारित रैंडम प्रणाली से किया जाएगा।
- स्क्रूटनी प्रक्रिया फेसलेस माध्यम से संचालित होगी, जिससे करदाताओं एवं विभागीय आधिकारियों के बीच अनावश्यक प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता कम होगी तथा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनेगी।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित शेष स्क्रूटनी प्रकरणों का रैंडम आधार पर आवंटन किया गया है।
- जिन करदाताओं के प्रकरण स्क्रूटनी के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें नियमानुसार पोर्टल से सूचित किया जाएगा।
- करदाताओं द्वारा समुचित कार्यवाही न किए जाने पर अग्रिम कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- **सौर ऊर्जा का नया अध्याय शुरू, 128 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से राजस्थान का ऐतिहासिक समझौता हुआ; प्रदेश बना पहला साझेदार, 125 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य–**

राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई वैश्विक पहचान हासिल करते हुए देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने 128 सदस्य देशों वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) के साथ 'फ्रेमवर्क फॉर एक्शन–एडवांस क्लीन एनर्जी, ड्रिवन सस्टेनेबल डवलपमेंट' पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से राजस्थान परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

की ओर तेजी से बढ़ेगा। वर्ष 2030 तक 125 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सौर ऊर्जा एकीकरण और सहायक नीतियों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इस प्रकार का फ्रेमवर्क फॉर एक्शन हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत भी वैश्विक स्तर पर दूसरे पायदान पर पहुँच चुका है।

2035 तक का बनेगा ऊर्जा रोडमैप–इस साझेदारी के तहत वर्ष 2030-35 की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लिए व्यापक एनर्जी ट्रांजिशन प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा दक्षता, मांग प्रबंधन, निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान, ऊर्जा मॉडलिंग, संस्थागत क्षमता निर्माण और आवश्यक नीतिगत सुधारों को शामिल किया जाएगा।

■ **राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ–**

राजस्थान द्वारा हाल ही में पार्वती-कालीसिंध एवं चम्बल नदियों के जल के बेहतर उपयोग के लिए एमपीकेसी परियोजना तथा हथिणीकुंड बैराज से राजस्थान के शेखावाटी अंचल में जल उपयोग को लेकर हाल ही में ऐतिहासिक समझौते हुए हैं।

- हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।
- 7 जुलाई, 2026 को दिल्ली में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत में राज्यों की हिस्सेदारी से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों के अंतिम निपटारे (वन-टाइम सेटलमेंट) का मार्ग प्रशस्त करता है।
- मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान द्वारा सहभागिता एवं सहकारी संवाद की भावना से वर्षों से लंबित नर्मदा नदी के लंबित मुद्दों का समाधान संभव हो पाया है।
- इस समझौते से नर्मदा नदी के जल का बेहतर उपयोग होगा।
- नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979 में अवार्ड के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य जल आवंटन किया गया था।
- इस अवॉर्ड के तहत क्लॉज IV/5 के प्रावधान के अनुसार कोई भी राज्य मानसून काल के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग अपने राज्य में कर सकता है। यह अधिशेष जल उस राज्य के खाते में नहीं जोड़ा जाएगा।
- इससे पश्चिमी राजस्थान के वंचित क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

■ **राज्य में फेसलेस एवं रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा करदाताओं के लिए महत्त्वपूर्ण पहल–**

राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में फेसलेस एवं रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी व्यवस्था लागू करने की अभिनव पहल की है, जो देश में अपनी तरह की अग्रणी व्यवस्था है।

इस नई व्यवस्था के तहत कर विवरणियों की स्क्रूटनी के लिए प्रकरणों का चयन एवं आवंटन कम्प्यूटर आधारित रेंडम प्रणाली से किया जाएगा।

स्क्रूटनी प्रक्रिया फेसलेस माध्यम से संचालित होगी, जिससे करदाताओं एवं विभागीय अधिकारियों के बीच अनावश्यक प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता कम होगी तथा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनेगी।

Newspaper of 10 July, 2026

■ **हाल ही में शिक्षा विभाग ने लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब योजना में दो से अधिक संतान होने की शर्त समाप्त कर दी गई है। पूर्व में केवल दो बालिकाओं को ही योजना का लाभ देने का प्रावधान था। साथ ही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।**

उल्लेखनीय है कि 'लाडो प्रोत्साहन योजना' बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। पात्र बालिकाओं को 1.50 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाता है।

■ **हाल ही में की गई केन्द्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के अनुसार कोटा (राजस्थान) से इटावा (उ.प्र.) तक चंबल नदी के समानान्तर एक नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम पूर्व प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस-वे हाइवे के स्थान पर अटल एक्सप्रेस-वे होगा।**

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

Newspaper of 11 July, 2026

■ **नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने 4 पदक जीत कर इतिहास रचा–**

हाल ही में हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन कर एक स्वर्ण, एक रजत व दो कांस्य पदक जीते। 113 अंकों के साथ राजस्थान ने पहली बार टीम चैंपियनशिप में देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर नया इतिहास रचा। 68 किग्रा वर्ग में अश्विनी विश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता। 50 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल में कोमल वर्मा ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि 57 किग्रा में निशा सैनी और 72 किग्रा में माया माली ने कांस्य पदक जीते।

■ **राष्ट्रीय योजनाएँ और नवाचार लागू करने में राजस्थान अव्वल रहा–**

राजस्थान सहकारिता क्षेत्र की राष्ट्रीय योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान अन्न भंडारण क्षमता, ई-पैक्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एम-पैक्स के गठन जैसी कई योजनाओं में प्रथम स्थान पर है।

- किसी भी देश या प्रदेश को वास्तविक विकास या समृद्धि प्राप्त करनी है, सहयोग और मिलकर काम करने की भावना जरूरी है।
- 'सहकार से समृद्धि' की इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री द्वारा 6 जुलाई, 2021 को शुरू किए गए सहकारिता मंत्रालय के जरिए देशभर के सहकारिता क्षेत्र में आई अभूतपूर्व क्रांति में राजस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

■ **ई-पैक्स से ऑनलाइन लेनदेन और एम-पैक्स गठन में प्रथम स्थान–**

- प्रथम चरण में चिह्नित 6 हजार 781 पैक्स में से 5 हजार 646 ई-पैक्स बनाए जा चुके हैं, जिनके जरिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन-देन हुए हैं, जो देश के कुल ट्रांजेक्शन का लगभग एक तिहाई होने के साथ सभी राज्यों से ज्यादा हैं।
- हर पंचायत में सहकारी समिति गठन की महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 5 हजार 279 नई बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है।
- इनमें 1 हजार 977 एम-पैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
- 'वोकल फॉल लोकल' के मंत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा सहकारी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला और संभागीय सहकारी मेलों का आयोजन किया गया है।
- 'श्री अन्न' पहल में सहभागिता निभाते हुए प्रदेश में 240 श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं, जिनसे पोषण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

गौरतलब है कि अन्न भंडारण योजना में भी राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।

Newspaper of 12 July, 2026

■ **जयपुर में देश का पहला एडवांस्ड रोबोटिक रिसर्च सेंटर शुरू हुआ–**

11 जुलाई, 2026 को जयपुर में देश के पहले एडवांस्ड रोबोटिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ। अब तेल-गैस के कुएँ, रिफाइनरियाँ, पावर हाउस, स्टील फैक्ट्रियाँ और सीवर लाइन जैसे जानलेवा स्थानों पर अब सिर्फ रोबोट काम करेंगे। राइजिंग राजस्थान के तहत इसका एमओयू हुआ था। सेंटर में एआई, एडवांस्ड सेंसर से लैस रोबोट विकसित किए जायेंगे।

■ **राज्य के विकास में योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को नया मंच मिलेगा–**

राज्य के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तियों की पहचान कर, उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल शुरू की गई है।

- इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।
- खास बात यह है कि 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा।
- राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति 15 अगस्त, 2026 तक विभाग की वेबसाइट (industries.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस पहल के तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता, शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने वाले व्यक्ति पात्र होंगे।
- चयनित व्यक्तियों को 'द 100 आइकन्स कम्पेंडियम' में स्थान दिया जाएगा।

Newspaper of 14 July, 2026

■ **सीमावर्ती बाड़मेर जिले के खड़ीन गाँव की मंजू जांगिड़ का चयन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत अफ्रीकी देश**

कांगो में तैनाती के लिए हुआ है। बीएसएफ की 160 सदस्यीय 19वीं टुकड़ी के साथ रवाना हुई 24 महिला जवानों में मंजू भी शामिल है।

■ **राजस्थानी संगीतकार के.सी. मालू का निधन हुआ–**

13 जुलाई, 2026 को राजस्थान के जाने माने संगीतकार के.सी. मालू (80) का निधन हो गया। राजस्थान रत्न से सम्मानित मालू ने बिना किसी सरकारी सहायता के पाँच हजार से अधिक लोकगीतों की पांडुलिपि ध्वनिलिपि तैयार कर ऑडियो रिकॉर्डिंग की। के.सी. मालू को समग्र कला साधना अवॉर्ड और डागर घराना अवार्ड मिल चुका है।

Newspaper of 16 July, 2026

■ **श्रम नियोजन में राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर रहा–**

वीबी जी राम जी योजना में श्रम नियोजन (लेबर डिप्लोयमेंट) में राजस्थान देशभर में पहले स्थान पर है।

- इस योजना में कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- योजना के कार्यों में मैपिंग एवं रिकॉर्ड संधारण सहित आधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। ताकि कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहें तथा प्रभावी सोशल ऑडिट संभव हो सके।
- साथ ही, योजना के तहत स्वीकृत होने वाले कार्य स्थानीय आवश्यकताओं एवं ग्रामीणों की प्राथमिकताओं के अनुरूप करवाये जा रहे हैं।
- यह योजना सतत् और सुदृढ़ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के तहत कार्यों के निष्पादन की अनुमति देती है।
- जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
- मौसम से बचाव संबंधी कार्य
- 12,636 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना के लिए वर्ष 2026-27 में
- 60 दिनों का राज्य सरकार कार्य विराम घोषित कर सकती है फसल बुवाई-कटाई के समय
- 125 दिन सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी
- 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हाल के मनरेगा औसत की तुलना में राज्यों को मिलने की उम्मीद
- 9 प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाया गया

■ **भारत टेक्स 2026 में गुलाबी नगर की थीम पर राजस्थान पैवेलियन तैयार हुआ–**

नई दिल्ली में 14 से 17 जुलाई तक आयोजित भारत टेक्स 2026 में राजस्थान सरकार का पैवेलियन देश-विदेश से आए खरीदारों, उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

- लगभग 209 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थापित इस पैवेलियन को जयपुर के गुलाबी नगर की थीम पर तैयार किया गया है।
- इसका भव्य प्रवेश द्वार ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाया गया है, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत की झलक प्रस्तुत करता है।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तथा राजसिको के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ है।

■ **राजस्थान ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास रचा, एक हजार मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर स्थापित–**

राजस्थान ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए 1,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का कीर्तिमान हासिल किया है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2,65,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कुल स्थापित क्षमता 1001.57 मेगावाट तक पहुँच गई है।

Newspaper of 18 July, 2026

■ **राजस्थान सरकार 15 अगस्त, 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के करीब 2500 गाँवों में समयबद्ध तरीके से 'जल अर्पण' कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके तहत पूरी हो चुकी पेयजल योजनाओं का ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को हस्तांतरण किया जाएगा।**

Newspaper of 19 July, 2026

■ **वैज्ञानिकों ने विकसित की सरसों की सीएस-68 किस्म, प्रति हैक्टेयर 22 क्विंटल तक पैदावार देगी–**

फतेहपुर कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने आईसीएआर करनाल के साथ मिलकर 6 साल के लंबे रिसर्च के बाद सरसों की हाइब्रिड किस्म सीएस-68 विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने 15 जुलाई, 2026 को इसकी मंजूरी दे दी। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्रतिकूल और सर्द-गर्म जलवायु में भी सामान्य सरसों के मुकाबले दो गुनी यानि प्रति हैक्टेयर 22 क्विंटल तक पैदावार देगी। सरसों की सामान्य किस्मों से प्रति हैक्टेयर 12 क्विंटल व हाइब्रिड किस्मों से अधिकतम 16 क्विंटल तक पैदावार मिल रही है। जबकि सीएस-68 किस्म से देशभर में किसान प्रति हैक्टेयर 22 क्विंटल तक पैदावार ले सकेंगे।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

Newspaper of 20 July, 2026

- **बाड़मेर (राजस्थान) के अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार उस्ताद समंदर खान मांगणियार को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक, अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगस्त, 2026 माह में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू उन्हें यह सम्मान प्रदान करेंगी।**
- **निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन; नियमों के सरलीकरण में देश में दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा स्थान–**

राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण मुहर लगी है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को 'अग्रणी राज्य' की श्रेणी में स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग में राज्य देशभर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा। वहीं, बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में राजस्थान ने दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का परिणाम है।

- **राज निवेश पोर्टल : अब 18 विभागों की 90 सेवाएँ उपलब्ध–**

राज्य सरकार ने निवेशकों को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार सुदृढ़ किया है।

वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएँ उपलब्ध हैं।

Newspaper of 21 July, 2026

- **राजस्थान निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में संभावित चुनाव कार्यक्रम दिया। निकायों के चुनाव 2 चरण में, पंचायतों के 4 चरण में होंगे–**

20 जुलाई, 2026 से हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 17 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी जाएगी। यह संभावित कार्यक्रम पेश होने पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाए। निकायों के चुनाव 2 चरण में और पंचायतों के 4 चरण में होंगे।

पंचायती राज संस्थाएँ (54 दिन)

- **चुनाव घोषणा :** 23 सितम्बर
- **निर्वाचन की अधिसूचना :** 28 सितम्बर
- **नामांकन की अंतिम तिथि :** 1 अक्टूबर अपराह्न 03:00 बजे तक
- **नाम वापसी की तिथि :** 5 अक्टूबर अपराह्न 3:00 बजे तक

मतदान दल रवानगी

- **प्रथम चरण :** 12 अक्टूबर
- **द्वितीय चरण :** 22 अक्टूबर
- **तृतीय चरण :** 28 अक्टूबर
- **चतुर्थ चरण :** 2 नवम्बर

उपसरपंच

- **प्रथम चरण :** 15 अक्टूबर
- **द्वितीय चरण :** 25 अक्टूबर
- **तृतीय चरण :** 31 अक्टूबर
- **चतुर्थ चरण :** 5 नवम्बर
- **मतदान :** प्रात: 7 से सायं 6 बजे तक

मतदान-मतगणना (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य)

- **प्रथम चरण :** 13 अक्टूबर
- **द्वितीय चरण :** 23 अक्टूबर
- **तृतीय चरण :** 29 अक्टूबर
- **चतुर्थ चरण :** 3 नवम्बर
- **मतगणना :** 12 नवम्बर

पंच/सरपंच

- **प्रथम चरण :** 14 अक्टूबर
- **द्वितीय चरण :** 24 अक्टूबर
- **तृतीय चरण :** 30 अक्टूबर
- **चतुर्थ चरण :** 4 नवम्बर
- **प्रमुख/प्रधान का चुनाव :** 14 नवम्बर
- **उप प्रमुख/उप प्रधान का चुनाव :** 15 नवम्बर
- **नामांकन :** सुबह 10 से 11 बजे तक

- **राजस्थान में 'साइबर सुरक्षा अभियान' शुरू हुआ–**

20 जुलाई, 2026 को साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'साइबर सुरक्षा अभियान' शुरू हुआ। सीएम ने पोस्टर का विमोचन कर इस अभियान की शुरुआत की।

- **राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का शुभारम्भ हुआ–**

21 जुलाई, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेल-खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री युवा सुयोग का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म एक सही दिशा, सही अवसर और सही मंच उपलब्ध कराएगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे सामूहिक खेलों के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व विकसित होगा और वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे।
- इस प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि युवाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

Newspaper of 22 July, 2026

राजस्थान में अब दो से अधिक संतान वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे–

राजस्थान में करीब 30 वर्ष बाद पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब दो या अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। इसकी पालना में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी अंडरटेकिंग लेने के 27 साल पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मार्च, 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित कानून लागू हो चुका है, इसलिए अब उम्मीदवारों पर दो-संतान की शर्त लागू नहीं होती।

गौरतलब है कि राज्य में करीब तीन दशक पहले कानून बनाकर दो या अधिक संतान वाले लोगों के पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी।

RCDF दुग्ध पैकेजिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में ₹ 150 करोड़ का पॉलीफिल्म प्लांट लगाएगी–

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) दूध पैकेजिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जयपुर डेयरी सहित प्रदेश की सभी सरकारी डेयरियों में दूध, घी और अन्य दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में उपयोग होने वाली पॉलीफिल्म अब आरसीडीएफ खुद तैयार करेगा। इसके लिए जयपुर में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक पॉलीफिल्म प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट की स्थापना और संचालन के लिए आरसीडीएफ जल्द ही हिंदुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरएल) के साथ एमओयू करेगा। कच्चे माल की आपूर्ति भी एचआरएल ही करेगा। प्रस्तावित प्लांट की क्षमता 20 मीट्रिक टन पॉलीफिल्म प्रतिदिन होगी। वर्तमान में जयपुर डेयरी सहित प्रदेश की सरकारी डेयरियों में प्रतिदिन औसतन 45 लाख लीटर दूध का संग्रहण और प्रोसेसिंग होती है। इसकी पैकेजिंग के लिए रोजाना करीब 14 मीट्रिक टन पॉलीफिल्म की जरूरत पड़ती है। भविष्य में दूध संग्रहण 65 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने के लक्ष्य को देखते हुए अधिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

एक नजर में परियोजना

परियोजना लागत	– करीब 150 करोड़ रुपए
स्थान	– जयपुर
उत्पादन क्षमता	– 20 मीट्रिक टन पॉलीफिल्म प्रतिदिन
वर्तमान जरूरत	– 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन
वर्तमान दूध संग्रहण	– 45 लाख लीटर प्रतिदिन
भविष्य का लक्ष्य	– 65 लाख लीटर प्रतिदिन
कच्चे माल की आपूर्ति	– हिंदुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड
वित्तीय स्रोत	– डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड

Newspaper of 23 July, 2026

जयपुर मेट्रो फेज-2 का भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारम्भ हुआ–

22 जुलाई, 2026 को जयपुर मेट्रो फेज-2 का भूमि पूजन के साथ ही इस परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ हो गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा-बंबाला पुलिया के पास प्रस्तावित मेट्रो डिपो स्थल का भूमि पूजन किया।

जयपुर मेट्रो फेज-2 एक नजर में–

- 41.64 किमी. लंबा विशाल कॉरिडोर बनेगा सीतापुरा से टोड़ी मोड़ तक।
- 13 हजार 37 करोड़ रुपए परियोजना की कुल लागत।
- 36 स्टेशन बनाए जाएंगे पूरे रूट पर, 34 एलीवेटेड, 2 भूमिगत।
- 2031 दिसम्बर तक कार्य पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित।

प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई-नीलामी में राजस्थान देशभर में अव्वल रहा–

हाल ही में हुई प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के साथ राजस्थान ने प्रधान खनिजों की नीलामी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।

- खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा ई-नीलाम किए गए 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों में से 105 खनिज ब्लॉकों की माइनिंग लीज और 30 खनिज ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है। इसके अलावा एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है।
- इनमें से राजस्थान से ही 7 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की गई है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- राज्य में ई-नीलामी प्रक्रिया लागू होने के बाद से अब तक सर्वाधिक 101 लाइमस्टोन के ब्लॉकों की नीलामी हुई है।
- इसके अलावा आयरन ओर के 13, बेसमेटल के 8, सिलियस अर्थ के 4, मैगनिज के 3, गोल्ड के 2, पोटाश एवं हैलाइट के 2, रेयर अर्थ एलिमेंट के 4 और गार्नेट, एमरल्ड, फ्लोराइट और रॉक फास्फेट के एक-एक ब्लॉकों की नीलामी हुई है।

गौरतलब है कि खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 55 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू किया है।

- **प्रदेश में एक करोड़ से अधिक नए पात्र लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा–**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश में 1 करोड़ 56 हजार 511 नए जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। गिव अप अभियान ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और करीब 93.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से गरीबों के हक में खाद्य सुरक्षा छोड़ी। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 1 नवम्बर 2024 को गिव अप अभियान प्रारंभ कर सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। करीब 3 माह बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया गया, ताकि वंचित लोग जुड़ सकें। पोर्टल खुलने के बाद 87 लाख 60 हजार 847 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया। इससे पहले भी वर्तमान सरकार के कार्यक्रम में 12 लाख 95 हजार 664 लोगों को योजना में जोड़ा गया था।

गिव अप अभियान के कारण 93 लाख 48 हजार 596 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। इससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत चलाए गए गिव अप अभियान में 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी थी।

- **हाई रिस्क गर्भवती महिला के लिए शुरू होगी 'प्रसव सखी' व्यवस्था–**

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम (हाई रिस्क) वाली गर्भवती महिलाओं को बेहतर सहयोग, मार्गदर्शन और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 'प्रसव सखी' व्यवस्था शुरू की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों तथा अधिक प्रसव भार वाले प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पेशेंट सेंट्रिक, रिस्पॉन्सिव, समन्वित और सम्मानजनक बनाना है।

ये 3 तरह के कर्मचारी होंगे प्रसव सखी– नई व्यवस्था के तहत 3 तरह के कर्मचारी प्रसव सखी के रूप में काम करेंगे। पिंक एप्रिन में तैनात प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी, एएनएम अथवा अन्य चयनित महिला स्वास्थ्यकर्मी 'प्रसव सखी' के रूप में कार्य करेंगी। वे अस्पताल पहुँचने वाली हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ भर्ती से लेकर प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और डिस्चार्ज तक हर चरण में सहयोग करेंगी। पंजीयन, जाँच, चिकित्सकीय परामर्श, उपचार, विशेषज्ञ सेवाओं से जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर रेफरल प्रक्रिया में भी समन्वय सुनिश्चित करेंगी।

Newspaper of 24 July, 2026

- **ई-मित्र वॉट्सएेप सेवा का सेवा दायरा बढ़ा, घर बैठे मिलेंगी 72 सरकारी सुविधाएँ; विद्युत वितरण निगम एवं स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएँ हुई शामिल–**

राज्य सरकार की ओर से नागरिकों को घर बैठे त्वरित एवं पारदर्शी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम तथा स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएँ भी जोड़ी गई हैं। पहले चरण में इस सेवा से 51 सरकारी सेवाएँ जोड़ी गई थीं। अब नई सेवाओं के जोड़ने के बाद मिलने वाली सेवाओं की संख्या 72 हो गई हैं। 1 जुलाई को 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस' के दौरान ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ के बाद से ही नागरिकों का इस सेवा के प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1.40 लाख से अधिक बार नागरिक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

राज्य सरकार की ओर से वॉट्सऐप नंबर 9461062705 जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर को मोबाइल में सेव करें 'Hi', 'Hello' संदेश भेजकर सेवा प्रारंभ कर सकते हैं, इसके बाद उपलब्ध सेवाओं की सूची में से आवश्यक सेवा का चयन कर कुछ ही क्लिक में संबंधित सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सेवा हिंदी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है। आगे के सभी विकल्प प्रदर्शित किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2026 में ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा पर 103 सेवाएँ शुरू कर दी गई हैं।

- **राजस्थान नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। राज्य में 1192 किमी. लंबाई के एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ है, जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। राज्यसभा में**

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने लिखित जवाब में बताया कि देशभर में 10,389 किमी. हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की मंजूरी मिली है, जिनमें से 4809 किमी. का निर्माण पूरा हो चुका है। देश में निर्मित कुल नेशनल एक्सप्रेस-वे का एक चौथाई हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है।

Newspaper of 25 July, 2026

- **टाइम आउट की ओर से जारी द वर्ल्डस हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 सूची में जयपुर को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर बताया गया–**

दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में अब जयपुर भी शुमार हो गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट की ओर से जारी द वर्ल्ड्स हैप्पिएस्ट सिटीज 2026 सूची में जयपुर को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर बताया गया है। खास बात यह है कि टॉप-10 में जगह बनाने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है। रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, जीवनशैली, स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी, पारंपरिक बाजार, खानपान और सामुदायिक जुड़ाव ने उसे दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शामिल कराया। पर्यटन और संस्कृति के साथ आधुनिक शहरी जीवन का संतुलन भी जयपुर की बड़ी ताकत माना गया है।

गुलाबी नगर के लिए ये उम्मीद–

- विदेशी पर्यटकों के बीच जयपुर की ब्रांड वैल्यू और मजबूत होगी।
- अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने शहर की सकारात्मक छवि बनेगी।
- पर्यटन, होटल, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
- स्टूडेंट्स, स्टार्टअप व प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षण बढ़ सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संभावनाएँ मजबूत होंगी।
- रहने योग्य शहर के रूप में जयपुर की पहचान और मजबूत होगी।
- वैश्विक मंच पर भारत की शहरी संस्कृति का सकारात्मक प्रतिनिधित्व।
- निकायों पर शहरी सुविधाएँ बेहतर बनाए रखने का दबाव भी बढ़ेगा।

शीर्ष 10 शहर–

- बाथ (ब्रिटेन)
- पनामा सिटी (पनामा)
- ग्वाडलाहारा (मेक्सिको)
- मेडेलिन (कोलंबिया)
- क्राको (पोलैंड)
- जयपुर (भारत)
- शिकागो (अमेरिका)
- केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका)
- शंघाई (चीन)
- गोथेनबर्ग (स्वीडन)

- **24 जुलाई, 2026 को हिंगोनिया गो पुनर्वास केन्द्र में 'अक्षय विद्यालय' की शुरुआत हुई। विद्यालय में संस्कारवान, चरित्रवान और राष्ट्रनिर्माण में योगदान देने वाले नागरिक तैयार किए जाएंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा, योग, पर्यावरण संरक्षण, गो-संवर्धन, अनुशासन, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष जोर रहेगा। पहले साल में पांचवीं तक के बच्चों को यहाँ निःशुल्क दाखिला मिलेगा।**
- **हाल ही में राजस्थान सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए नियमों में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। नए संशोधन के अनुसार अब निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली स्पॉन्सरिंग बॉडी के पास न्यूनतम 25000 वर्गमीटर कॉरपेट एरिया का निर्मित भवन और न्यूनतम 25000 वर्गमीटर खुला क्षेत्र होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने अब एक के बजाय दो अलग-अलग भूखंडों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की कुछ शर्तों के साथ छूट दी है।**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान पर राजस्थान–**

राज्य में जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने और तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए प्रभावी प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया है।
- नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान सरकार की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक डॉ. एस.एन. धोलपुरिया ने डब्ल्यूएचओ कंट्री हेड से यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया।

- **राजस्थान में 2.70 लाख रूफ टॉप सोलर प्लांट लगे; देश में पांचवें स्थान पर–**

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेश के घरों पर दो लाख 70 हजार 90 रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं। घरों की छत 1043 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट लगने से डिस्कॉम्स को दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो रही है। राज्य में अब तक दो लाख 79 हजार 50 उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर 1815 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

चुकी है। सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट जयपुर डिस्कॉम में 95 हजार 181 लगे हैं। वहीं जोधपुर डिस्कॉम में 84 हजार 995 और अजमेर डिस्कॉम में 89 हजार 912 प्लांट लगे हैं। प्रदेश में रोजाना 1200 सोलर प्लांट लग रहे हैं। योजना में अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगाने पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान देश में पांचवे स्थान पर है। राजस्थान से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व केरल में लग चुके हैं।

पाँच जिले सबसे आगे– पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में जयपुर जिला सबसे आगे है। जयपुर में 56 हजार 909 प्लांट लग चुके हैं। वहीं श्रीगंगानगर में 25 हजार 027, सीकर में 16 हजार 504 प्लांट, हनुमानगढ़ में 15 हजार 186 प्लांट और झुंझुनूं में 14 हजार 630 प्लांट लगे हैं।

सूर्यघर योजना में टॉप राज्य–

गुजरात	:	7,63,511
उत्तर प्रदेश	:	6,96,356
महाराष्ट्र	:	6,87,838
केरल	:	3,03,693
राजस्थान	:	2,70,090
आंध्र प्रदेश	:	2,47,816

■ ई-जीरो FIR लागू, 30 घंटे में स्वतः दर्ज हुई 13 एफआईआर–

साइबर ठगों पर डिजिटल स्ट्राइक करने के लिए राजस्थान पुलिस ने 1930 हेल्पलाइन पर मिलने वाली सूचनाओं में 1 लाख से ज्यादा की ठगी के संबंध में ई-जीरो एफआईआर प्रणाली लागू की थी। ये प्रणाली पहले 5 लाख रुपए की ठगी पर लागू थी। नई प्रणाली लागू होने के पहले ही दिन 30 घंटे में 13 एफआईआर दर्ज की गई। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि साइबर ठगी के पैसों का मूवमेंट रोकने और प्रभावी अनुसंधान के लिए ई-जीरो एफआईआर स्कीम लागू की थी। इसके सही परिणाम भी मिले हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन 1930 और सीसीटीएनएस को आपस में जोड़ दिया। अब 1930 पर मिलने वाली साइबर ठगी की शिकायतों में ठगी का अमाउंट 1 एक या उससे ऊपर होगा तो एआई तकनीक से ऑटोमेटिक ई-जीरो एफआईआर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। दर्ज होने के बाद सबंधित थाने को फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसे में पीड़ितों को थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे ठगी के पैसे जाने वाले बैंक खातों को फ्रीज कराने और ठगी के पैसे रिफंड कराने में मदद मिलेगी।

■ थार मरुस्थल में तैयार हुई 28 किमी परिधि की कृत्रिम झील; 1406 एमसीएफटी पानी होगा स्टोरेज–

राजस्थान के जैसलमेर जिले के घांटियाली क्षेत्र में तैयार हुआ बुर्जी-1356 एस्केप रिजर्वायर अब 28 किलोमीटर की परिधि वाली कृत्रिम झील का रूप ले चुका है। हर साल मानसून के दौरान इंदिरा गाँधी नहर प्रणाली से अतिरिक्त बहाव के रूप में निकलकर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को यहाँ स्टोर किया जाएगा। यह जैसलमेर-बाड़मेर सहित गाँवों की पानी की माँग को पूरा करेगा।

■ नशे की सूचना को हेल्पलाइन 8764866939 नंबर जारी–

राजधानी जयपुर को नशा मुक्त बनाने, साइबर सुरक्षा और कानून व्यवस्था में मदद और कम्यूनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए 24 जुलाई, 2026 को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने नगर निगम सभागार में परकोटे की सीएलजी मीटिंग ली। बैठक में माणकचौक, रामगंज व सुभाष चौक क्षेत्रों के सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियाँ सहित कई लोग शामिल हुए। इसमें कानून-व्यवस्था, नशा मुक्ति अभियान के साथ-साथ महिला सुरक्षा और परकोटे की यातायात व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में कमिश्नर बोले, सीएलजी सदस्यों के सुझावों से सामुदायिक पुलिसिंग मजबूत होगी। कमिश्नर ने नशे से जुड़ी सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14446, 1933 और 8764866939 की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

Newspaper of 26 July, 2026

■ राजस्थान में भारत टैक्सी सेवा का शुभारम्भ जयपुर से हुआ–

25 जुलाई, 2026 से सहकारिता मॉडल पर शुरू हुई भारत टैक्सी सेवा का आगाज राजस्थान में जयपुर से हुआ। अभी तक यह सेवा ट्रायल बेस पर चल रही थी। टैक्सी चलाने वाले चालकों की कमाई में अब किसी बिचौलिए का हिस्सा नहीं होगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने 100 से अधिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत टैक्सी में सारथी खुद मालिक हैं। क्योंकि शेयर लेने वाले चालकों को लाभांश में भी हिस्सा मिलेगा। इस योजना का विस्तार 500 शहरों में करने का लक्ष्य है।

■ जयपुर के सुमेल गाँव में 64 एकड़ में विकसित होगा सहकार वन–

25 जुलाई, 2026 को जयपुर के सुमेल गाँव में करीब 64 एकड़ में विकसित होने वाले 'सहकार वन' की शुरुआत पौधरोपण के साथ हुई। अमूल एवं एनसीसीएफ के सहयोग से सहकारिता विभाग के इस हरित प्रोजेक्ट में मियावाकी और पारंपरिक दोनों तकनीकों से स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए

जाएंगे। इसमें खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम और कई तरह के फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं।

Newspaper of 28 July, 2026

टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम, 7 अगस्त तक चलेगा अभियान–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''टीबी मुक्त भारत'' संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

- राज्य सरकार ''निरामय राजस्थान'' की परिकल्पना के अनुरूप टीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रोग की शीघ्र पहचान, समयबद्ध जाँच, नि:शुल्क उपचार, पोषण सहायता और जनभागीदारी आधारित गतिविधियों को मिशन मोड में संचालित कर रही है।
- राज्य सरकार की रणनीति केवल टीबी का उपचार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ते हुए हर छिपे हुए मरीज तक पहुँचना है।
- इसी सोच के साथ 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

100 दिवसीय विशेष अभियान–

- 35.86 लाख लोगों की हुई स्क्रीनिंग
- 28.91 लाख लोगों के घर-घर पहुँची टीमें
- 9,949 आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन

महत्त्वपूर्ण उपलब्धि–

- 49,703 नए टीबी मरीजों की हुई पहचान
- 6,574 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

जन-धन योजना में राजस्थान तीसरे स्थान पर–

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य में अब तक 3.85 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 24,610 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि है। अगस्त 2014 में शुरू हुई पीएम जन-धन योजना के तहत खातों में जमा राशि लगातार बढ़ रही है। राज्य में 2.19 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते हैं, जो कुल खातों का 57 प्रतिशत है। इन खातों के जरिए महिलाओं को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। योजना के तहत राजस्थान में 2.87 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जन-धन योजना में उत्तर प्रदेश पहले व बिहार तथा पश्चिम बंगाल संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।

27 जुलाई, 2026 को दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर कोटा जिला स्थित मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही टनल की एक ट्यूब (मुम्बई से दिल्ली) पर यातायात शुरू कर दिया गया। यह देश की पहली आठ लेन वाली सड़क टनल है। इसके शुरू होने से दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा का समय करीब 45 मिनट कम हो जाएगा। इस 8 किमी. के पैकेज को वाहन चालक महज 5 से 6 मिनट में पार कर सकेंगे। वर्तमान में यातायात दराघाटी से होकर गुजरता है। पहले 28 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब यह दूरी घटकर केवल 8 किमी. रह जाएगी।

एसपीएल भारत कप 2027 का आयोजन फरवरी-मार्च 2027 में होगा। आठ राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी–

एसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण का नाम अब एसपीएल भारत कप 2027 होगा। यह टूर्नामेंट फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित होगा। इसमें आठ राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। इस बार इस टूर्नामेंट के मुकाबले सिंथेटिक लेदर गेंद से खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की कुल ईनामी राशि 31 लाख रुपए रखी गई है। इस टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य देशभर के युवा क्रिकेटरों को प्रतिभा दिखाने और भविष्य में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में मंच उपलब्ध कराना है।

राजस्थान के 85 हजार सरकारी भवन 'सोलर पावर हाउस' बनेंगे–

राजस्थान में सरकारी भवनों के बिजली बिल को शून्य करने की दिशा में अभियान तेजी से बढ़ रहा है। करीब 85 हजार भवन, जिनमें 5 किलोवाट या उससे अधिक लोड के बिजली कनेक्शन हैं, उनकी छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 2,152 सरकारी भवनों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 23 जिला कलेक्ट्रेट भी शामिल हैं। राज्य में करीब 1.96 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन हैं।

नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रैंडलीनेस इंडेक्स-2026 में राजस्थान बड़े राज्यों में 8वें और देशभर में 10वें स्थान पर–

नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में राजस्थान ओवरऑल 10वें स्थान पर है। राज्य को 48.1 अंक मिले हैं, जिसके आधार पर वह देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 10वें तथा बड़े 17 राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, नियामकीय सुगमता और उद्योग समर्थक सरकारी नीतियाँ हैं, जबकि बिजनेस क्लाइमेट, संस्थागत व्यवस्था और वित्तीय स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ अभी उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी, प्रति व्यक्ति GSDP 1.22 लाख रुपए, कृषि का जीवीए में 12.7%, उद्योग का 28.4% तथा सेवा क्षेत्र का 58.9%

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

योगदान है। वर्ष 2023-24 में राज्य में 265.43 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया। प्रमुख उद्योगों में बेसिक मेटल्स, फूड प्रोसेसिंग और केमिकल्स शामिल हैं।

खनिज उत्पादन में आगे–रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान देश के कुल गैर-धात्विक खनिज उत्पादन का 33% और धात्विक खनिज उत्पादन का 14% हिस्सा रखता है। निर्माण कार्यों के लिए परमिट जारी करने और वेयरहाउसिंग क्षमता में भी राज्य का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है।

सड़क-रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक में बेहतर–रिपोर्ट में निवेशकों ने राजस्थान की बेहतरीन सड़क एवं रेल नेटवर्क, आधुनिक औद्योगिक पार्क, मजबूत लॉजिस्टिक्स और डिजिटल अवसरंचना की सराहना की है। साथ ही सुझाव दिया कि सरकार को निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का अधिक प्रचार, अनुमोदन प्रक्रिया का और डिजिटलीकरण तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान की स्थिति–

- **कुल स्कोर :** 48.1
- **देश में रैंक :** 10वाँ
- **बड़े राज्यों में रैंक :** 8वाँ
- **FDI (FY24) :** 265.43 मिलियन डॉलर
- **प्रति व्यक्ति GSDP :** 1,22,629 रुपए
- **सबसे मजबूत पक्ष :** नियामकीय सुगमता, सरकारी नीति और प्राकृतिक संसाधन।
- **सबसे बड़ी चुनौती :** बिजनेस क्लाइमेट और उद्योगों को बैंक क्रेडिट बढ़ाना।

Newspaper of 29 July, 2026

■ राजस्थान के 11 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के अध्ययन केन्द्र खुलेंगे–

हाल ही में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के 11 प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं को राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र खोलने की तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकभवन की ओर से विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि राज्य में बड़े भू-भाग पर राजस्थानी भाषा बोली जाती है और यह स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। राज्य के प्रमुख निम्न 11 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा केन्द्र स्थापित किए जाएँगे–

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
- मोहनलाल सुखाड़िया वि.वि., उदयपुर
- एमडीएस वि.वि., अजमेर
- कोटा वि.वि., कोटा
- महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर
- वर्धमान महावीर खुला वि.वि., कोटा
- गोविन्द गुरु जनजातीय वि.वि., बांसवाड़ा
- पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी वि.वि., सीकर
- महाराजा सूरजमल बृज वि.वि., भरतपुर
- राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य वि.वि., अलवर

Newspaper of 30 July, 2026

■ देश का पहला रेयर अर्थ खनिज खोज लाइसेंस राजस्थान में दिया गया; बालोतरा-जोधपुर में होगी रेयर अर्थ की तलाश/खोज–

हाल ही में राजस्थान ने खनिज क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट (आरईई) खोज लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह लाइसेंस बालोतरा और जोधपुर जिले के 207.63 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। यहाँ रेयर अर्थ खनिजों की वैज्ञानिक तरीके से खोज की जाएगी। इस क्षेत्र में लैथेनम, सीरियम, प्रजोडायमियम और नियोडिमियम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज मिलने के संकेत हैं।

उल्लेखनीय है कि रेयर अर्थ एलिमेंट मॉर्डन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार सहित अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज है।

Newspaper of 31 July, 2026

■ राजस्थान के आठ जिलों में स्थायी लोक अदालत खुलेंगी–

राजस्थान में छोटे-छोटे विवादों के निपटारे को आसान और सस्ता बनाने के लिए आठ जिलों में स्थायी लोक अदालतें खुलेंगी। इन जिले के लोगों को अपने मामलों के समाधान के लिए दूसरे जिलों या लंबी न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

राज्य सरकार ने फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर में लोक अदालतें खोलने का फैसला लिया है।

■ 9 अगस्त, 2026 से 17 अगस्त, 2026 तक हर घर फहरेगा तिरंगा, 'सेल्फी विद तिरंगा' अभियान चलेगा–

राजस्थान में 80वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2026) का मुख्य समारोह इस बार बीकानेर में होगा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में राज्यभर में 9 अगस्त से 17 अगस्त, 2026 तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलेगा। 14 अगस्त को पहली बार 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' भी मनाया जाएगा।

□□□

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

51 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

आगामी परीक्षाओं हेतु राजस्थान सामान्य ज्ञान PYQ की श्रेष्ठ पुस्तकें
प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या

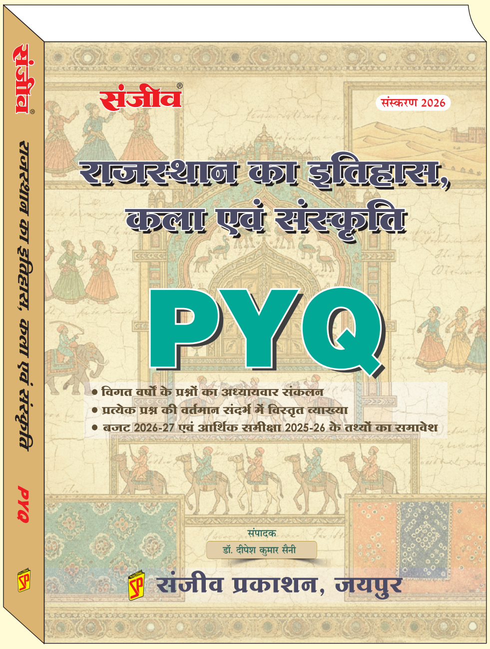

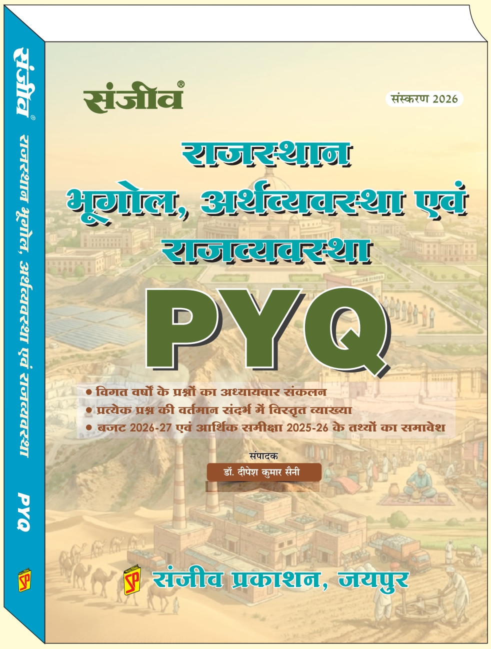

संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित अन्य प्रमुख पुस्तकें

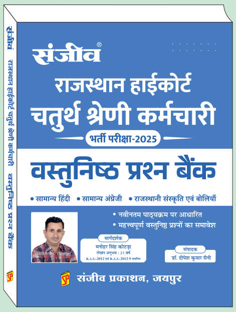

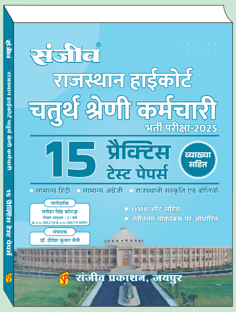

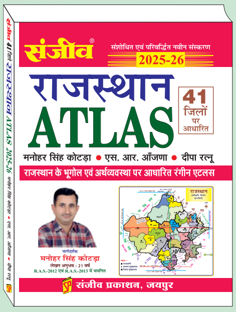

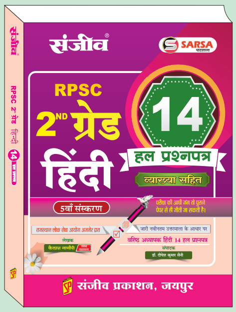

संजीव प्रकाशन

Join Our App

संजीव Telegram चैनल, App एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव App एवं वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।

संजीव प्रकाशन

Join Our Telegram

प्रकाशक-संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com